

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ**डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14701/2015**

मैसर्स रामप्रभु होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत में निगमित और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3-बीए-42, जवाहर नगर, जयपुर-302004 पर है, निदेशक अभिषेक खंडेलवाल के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव वित्त (कर) विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. संग्राहक (स्टाम्प), जिला अलवर, राजस्थान।
3. उप महानिरीक्षक स्टाम्प, पंजीकरण और स्टाम्प विभाग, अलवर, राजस्थान।
4. उप पंजीयक-I, अलवर।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में श्री रचित शर्मा श्री अभिषेक शर्मा
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री भरत व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता साथ में सुश्री अदिति वत्स

माननीय न्यायाधीश श्री अवनीश झिंगन**माननीय न्यायाधीश श्री आशुतोष कुमार****आदेश****21/02/2025****अवनीश झिंगन, न्यायाधीश**

1. यह याचिका संग्राहक (स्टाम्प), अलवर (संक्षेप में 'संग्राहक') द्वारा पारित दिनांक 03.08.2015 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) है। कंपनी ने खसरा संख्या 171, 212, 212/870, 212/871, 214, 215, और 212/869 वाली कृषि भूमि खरीदी, जो ग्राम लिवारी, जिला अलवर (जिसे इसके बाद 'संपत्ति' कहा जाएगा) में स्थित है। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में '1956 का अधिनियम') की धारा 90बी और नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (संक्षेप में '1959 का अधिनियम') की धारा 60 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, नगर सुधार न्यास, अलवर (जिसे इसके बाद 'यूआईटी' कहा जाएगा) ने दिनांक 25.01.2023 का आवंटन पत्र कंपनी के नाम पर जारी किया। दिनांक 05.04.2003 को यूआईटी द्वारा कंपनी के पक्ष में निन्यानवे वर्षों के लिए संपत्ति का पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। कंपनी को आवंटन निदेशकों श्री महावीर प्रसाद कट्टा, श्री प्रदीप कुमार कट्टा, श्री प्रेम नारायण गुप्ता और श्री योगेश चंद्र गुप्ता के माध्यम से हुआ था। कंपनी के निदेशकों ने अपने शेयरों को हस्तांतरित कर दिया और नए निदेशक नियुक्त किए गए।

2.1 संग्राहक ने 24.05.2004 को पूर्व निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए कि शेयरधारिता को हस्तांतरित करके कंपनी की संपत्ति के हस्तांतरण से स्टाम्प शुल्क की हानि हुई है। उत्तर दायर किया गया था कि संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था, शेयरों की बिक्री का कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं था और वर्तमान निदेशकों का विवरण प्रदान किया गया था। नए निदेशकों को दिनांक 21.10.2014 को

नोटिस जारी किए गए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि संपत्ति का हस्तांतरण समनुदेशन द्वारा पट्टे की श्रेणी में आता है। नोटिसों का जवाब 24.12.2014 को दिया गया था। संग्राहक ने संपत्ति का मूल्यांकन प्राप्त करने के बाद दिनांक 03.08.2015 का आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें ₹7,62,73,440/- की मांग की गई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यूआईटी ने कंपनी के पक्ष में संपत्ति का पट्टा विलेख निष्पादित किया। निदेशकों की शेयरधारिता नए निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गई थी लेकिन संपत्ति कंपनी की थी और कंपनी की ही रही। दलील यह है कि संपत्ति के हस्तांतरण के अभाव में स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जा सकता था। यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और रिट याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के पास 1998 के अधिनियम की धारा 65 के तहत पुनरीक्षण का उपाय है और इस आधार पर ही याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के हरदेव आसनानी बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 2011 एससी 3748; अंसल हाउसिंग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 13 एससीसी 305; जेनपैक्ट (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सीआईटी (2019) 419 आईटीआर 440 के निर्णयों और इस न्यायालय के दिनांक 01.08.2022 के डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 619/2022 परम प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम राजस्थान राज्य और अन्य शीर्षक वाले निर्णय और दिनांक 02.02.2024 के डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3730/2015 मनोज कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य शीर्षक वाले निर्णय पर भरोसा किया गया है।

4.1 इसके अलावा, पूर्व निदेशकों द्वारा नए निदेशकों को शेयरों के हस्तांतरण से कंपनी की पूरी संरचना बदल गई थी। निवेदन है कि स्टाम्प शुल्क से बचते हुए कंपनी की संपत्ति को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से निदेशकों को बदला गया था और यह निगम के आवरण को हटाने का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान राज्य बनाम गोटन खनिज उद्योग (2016) 4 एससीसी 469 में रिपोर्टेड निर्णय; कर्नाटक राज्य बनाम जे. जयललिता और अन्य (2017) 6 एससीसी 263 में रिपोर्टेड निर्णय पर भरोसा किया गया है।

4.2 राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 6, 2009 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी के कानूनी स्वरूप में बदलाव द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण समनुदेशन द्वारा पट्टे के शीर्ष के अंतर्गत आता है और स्टाम्प शुल्क देय है।

5. वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दा है:-

"क्या निदेशकों का बदलना कंपनी की संपत्ति के हस्तांतरण के बराबर है?"

6. यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और शेयरधारकों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1965 एससी 40, के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया था:

24. किसी निगम या कंपनी के स्वरूप के संबंध में सही कानूनी स्थिति, जिसका निगमन एक सांविधिक प्राधिकारी के कारण होता है, संदेह या विवाद में नहीं है। कानून में निगम एक

प्राकृतिक व्यक्ति के बराबर है और इसका अपना एक कानूनी अस्तित्व है। निगम का अस्तित्व इसके शेयरधारकों से पूरी तरह से अलग है; इसका अपना नाम और अपनी मुहर है; इसकी परिसंपत्तियां इसके सदस्यों की परिसंपत्तियों से अलग और विशिष्ट हैं; यह विशेष रूप से अपने उद्देश्यों के लिए मुकदमा कर सकती है और इस पर मुकदमा किया जा सकता है; इसके लेनदार इसके सदस्यों की परिसंपत्तियों से वसूली प्राप्त नहीं कर सकते हैं; सदस्यों या शेयरधारकों की देयता उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक सीमित है; इसी तरह, सदस्यों के लेनदारों का निगम की परिसंपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं है। यह स्थिति सलोमन बनाम सलोमन एंड कंपनी [1897 एसी 22 एचएल] के मामले में 1897 में सुनाए गए निर्णय के बाद से अच्छी तरह से स्थापित हो गई है; और वास्तव में, यह हमेशा से सामान्य कानून का एक सुविख्यात सिद्धांत रहा है। xx xx
xx

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम सचिव, राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (1999) 4 एससीसी 458:

15. एक कंपनी और उसके शेयरधारक के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए, भले ही वह शेयरधारक केवल एक हो और वह केंद्र या राज्य सरकार हो। कानून की नजर में, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी अलग कानूनी इकाई है जो उन कानूनी संस्था या संस्थाओं के अलावा है जो इसके शेयर रखते हैं।

7. पट्टा विलेख स्पष्ट है कि यूआईटी ने निदेशकों के माध्यम से कंपनी को संपत्ति पट्टे पर दी। कंपनी एक न्यायिक इकाई है लेकिन इसके गठन पर विचार करते हुए इसे अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करना होता है और इसलिए पट्टा विलेख कंपनी के पक्ष में था लेकिन निदेशकों के माध्यम से। प्रतिवादीगण ने राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की धारा 47 ए के तहत कार्यवाही शुरू करने में त्रुटि की,

यह मानते हुए कि पट्टा विलेख कंपनी के निदेशकों के पक्ष में था। पट्टा विलेख कंपनी के पक्ष में था और संपत्ति का स्वामित्व कंपनी के पास है।

8. इस प्रस्ताव पर कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति शेयरधारकों की संपत्ति नहीं है। इस संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के **मैकोरा बनाम नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड [1925] ए.सी. 619** के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया था:

माननीय न्यायाधीश, इस अपील का निपटारा यह कहकर किया जा सकता है कि निगम सदस्य, भले ही वह सभी शेयर रखता हो, निगम नहीं है, और न तो उसे और न ही कंपनी के किसी लेनदार को निगम की परिसंपत्तियों में कोई कानूनी या साम्यिक संपत्ति प्राप्त है।

8.1 सर्वोच्च न्यायालय ने बाचा एफ. गुज्दार बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे एआईआर 1955 एससी 74 में माना:

8. xx xx xx यह सच है कि कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी के मामलों के प्रशासन में एकमात्र निर्णायक आवाज प्राप्त है और वे संगठन के अंतर्नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लाभ में से शेयरधारकों को लाभांश वितरित किए जाने की घोषणा करने के हकदार हैं, लेकिन शेयरधारक का हित या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कंपनी के लाभ में भाग लेने के अधिकार से अधिक नहीं है। कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और शेयरधारकों से अलग है। यह कंपनी है जो संपत्ति की मालिक है न कि शेयरधारक। लाभांश कंपनी द्वारा शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने योग्य घोषित लाभ का एक हिस्सा है। xx xx xx

8.2 सर्वोच्च न्यायालय ने रुस्तम कावसजी कूपर और अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) [1970] 3 एससीआर 530 में माना:

14. कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है, जो अपने व्यक्तिगत सदस्यों से अलग और विशिष्ट है। कंपनी की संपत्ति शेयरधारक की संपत्ति नहीं है। एक शेयरधारक का कंपनी में केवल वही हित होता है जो

उसके अंतर्नियमों के तहत उत्पन्न होता है, जिसकी गणना देयता के उद्देश्य के लिए धन की राशि से और लाभ में एक हिस्से से की जाती है।

9. पूर्व निदेशकों द्वारा वर्तमान निदेशकों को शेयरधारिता का हस्तांतरण कंपनी की संपत्ति के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करता है। प्रतिवादी के अधिवक्ता की इस दलील में भ्रम है कि निदेशकों को बदलने से कंपनी की संपत्ति स्टाम्प शुल्क से बचते हुए हस्तांतरित हो गई और इसलिए निगमित आवरण को भेदना चाहिए। कंपनी की कानूनी स्थिति और स्वरूप जैसा था वैसा ही रहा और शेयरधारिता के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप केवल निदेशकों में बदलाव हुआ। कंपनी की संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ जिसके लिए स्टाम्प शुल्क देय था और निगमित आवरण को उठाने का कोई मामला नहीं बनता है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत राय सलूजा बनाम एयर इंडिया लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 407 में उन सिद्धांतों को दोहराया है जब निगमित आवरण को भेदा जा सकता है। प्रासंगिक भाग पुनरुत्पादित किया गया है:

68. हाल के समय में, मुनबी जे. द्वारा बेन हशेम बनाम अली शायफ (2008) ईडब्ल्यूएचसी 2380 (फैमिली) में तैयार किए गए छह सिद्धांतों के इर्द-गिर्द कानून स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है। मामले के अनुच्छेद 159-164 में पाए गए छह सिद्धांत निम्नलिखित हैं-

- (i) एक कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण निगमित आवरण को भेदने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे;
- (ii) न्यायालय कंपनी में किसी तृतीय पक्ष के हित न होने की स्थिति में भी, निगमित आवरण को भेद नहीं सकता, केवल इसलिए कि इसे न्याय के हित में आवश्यक माना जाता है;
- (iii) निगमित आवरण को केवल तभी भेदा जा सकता है जब कुछ अनुचितता शामिल हो;
- (iv) प्रश्नगत अनौचित्य को दायित्व से बचने या छिपाने के लिए कंपनी संरचना के उपयोग से जोड़ा जाना चाहिए;

(v) निगमित आवरण को भेदने को न्यायोचित ठहराने के लिए, दोषी (दोषियों) द्वारा कंपनी का नियंत्रण और अनुचितता दोनों होने चाहिए, अर्थात् उनके द्वारा अपने गलत काम को छिपाने के लिए एक साधन या मुखौटा के रूप में कंपनी का उपयोग या दुरुपयोग; और

(vi) कंपनी एक 'मुखौटा' हो सकती है, भले ही इसे मूल रूप से किसी भ्रामक इरादे से निगमित नहीं किया गया हो, बशर्ते कि प्रासंगिक लेन-देन के समय इसे धोखे के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा हो। हालाँकि, न्यायालय निगमित आवरण को केवल उतनी ही सीमा तक भेदेगा जितनी कि उस विशेष गलती के लिए एक राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हो जो कंपनी को नियंत्रित करने वालों ने की थी।

11. यह एक अविवादित तथ्य है कि वर्ष 2013-2014 में भी संपत्ति कंपनी की ऑडिट की गई बैलेंस शीट में दिखाई गई है। बल्कि बहस के दौरान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट पर भरोसा किया कि संपत्ति नए निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसे 31.03.2014 को तैयार कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है। यह दलील भ्रामक है, बैलेंस शीट कंपनी की है न कि निदेशकों की। संपत्ति कंपनी को पट्टे पर दी गई थी और निदेशकों के बदलने के बाद भी कंपनी की ही बनी हुई है।

12. परिपत्र 6, 2009 पर भरोसा करने से प्रतिवादीगण के मामले को बल नहीं मिलता है। परिपत्र का खंड 11 उन उदाहरणों से संबंधित है जहाँ पट्टे का हस्तांतरण समनुदेशन द्वारा हस्तांतरण माना जाएगा। पूरक दस्तावेज या संशोधित पट्टा विलेख के रूप में निष्पादित दस्तावेज जो साझेदारी में बदलाव या साझेदारी के विघटन या कंपनी के कानूनी स्वरूप में बदलाव का परिणाम है, समनुदेशन द्वारा पट्टे की श्रेणी में आएंगे।

13. इतना कहना पर्याप्त है कि शेयरधारिता में बदलाव से कंपनी का कानूनी स्वरूप नहीं बदला, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और ऐसी ही बनी हुई है। यह ध्यान देना उपयुक्त होगा कि यूआईटी और कंपनी के बीच पट्टा विलेख में कोई संशोधन नहीं हुआ था। पट्टा विलेख में निदेशकों के नाम का उल्लेख इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि संपत्ति का पट्टा कंपनी को दिया गया था।

14. पूर्ण निष्पक्षता के साथ निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, हमें वैकल्पिक उपचार की उठाई गई आपत्ति से निपटना चाहिए। वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता पर रिट अधिकार क्षेत्र में अहस्तक्षेप का प्रतिबंध एक स्व-आरोपित प्रतिबंध है।

15. सर्वोच्च न्यायालय ने *व्हालरूपल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य* (1998) 8 एससीसी 1, गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकारी और अन्य एआईआर 2023 एससी 781 और पीएचआर इन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी बनाम यूको बैंक और अन्य (2024) 6 एससीसी 579 के मामलों में वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए अपवाद निर्धारित किए हैं। पीएचआर इन्वेंट (उपरोक्त) से प्रासंगिक पैरा पुनरुत्पादित है:-

"37. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि न्यायालय ने कुछ अपवाद निर्धारित किए हैं जब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद स्वीकार किया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) जहाँ सांविधिक प्राधिकारी ने प्रश्नगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है;

- (ii) इसने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना में कार्य किया है;
- (iii) इसने उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जिन्हें निरस्त कर दिया गया है; और;
- (iv) जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है।

16. आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है और सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। निदेशकों द्वारा शेयरधारिता के हस्तांतरण पर सात करोड़ से अधिक की मांग इस त्रुटिपूर्ण आधार पर उत्पन्न की गई है कि कंपनी की संपत्ति नए निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गई थी।

17. विचार किया जाने वाला एक अन्य पहलू यह है कि पुनरीक्षण के उपाय का लाभ उठाने के लिए, पूर्व जमा करना आवश्यक है। **मैसर्स टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य; (2021) 12 एससीसी 477**, में पिछले निर्णय पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सांविधिक उपचार के रूप में अपील का लाभ उठाने के लिए पूर्व जमा की आवश्यकता वाले प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा। यह माना गया कि अपील का उपचार न तो प्राकृतिक है और न ही अंतर्निहित बल्कि एक सांविधिक अधिकार है और इसे शर्तों द्वारा सीमित किया जा सकता है। यह माना गया कि शक्ति के मनमाने उपयोग या अत्यधिक मांग के निर्माण के खिलाफ, जो उपचार को निष्फल बना देता है, से सुरक्षा के लिए, उपयुक्त मामलों में रिट अधिकार क्षेत्र का आवाहन किया जा सकता है। प्रासंगिक पैरा हैं:-

15. पी. लक्ष्मी देवी के मामले [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720] में, स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के प्रावधान की वैधता का मुद्दा था। उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान को असंवैधानिक माना था [पी. लक्ष्मी देवी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2001 एससीसी ऑनलाइन एपी 448 : एआईआर 2001 एपी 446], जिस विचार को इस न्यायालय ने उलट दिया था। उक्त धारा 47-ए का प्रावधान इस प्रकार है:

“बशर्ते कि पंजीकरण अधिकारी द्वारा कोई संदर्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्ष द्वारा उसके द्वारा

निकाले गए घाटे के शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर राशि जमा नहीं की जाती है।”

प्रासंगिक चर्चा निम्नानुसार थी: (पी. लक्ष्मी देवी का मामला [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720], एससीसी पृष्ठ 735-36, पैरा 18-23)

“18. हमारी राय में, आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम 8, 1998 द्वारा संशोधित धारा 47-ए के अधिनियमन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 या किसी अन्य प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं है। यह संशोधन केवल कमियों को दूर करने और स्टाम्प शुल्क की शीघ्र वसूली के लिए था। इसलिए यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 44 के साथ पठित सूची II की प्रविष्टि 63 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति के भीतर है।

19. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्टाम्प शुल्क एक कर है, और कठिनाई कर लगाने वाले कानूनों की व्याख्या करने में प्रासंगिक नहीं है, जिनकी सख्ती से व्याख्या की जानी है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कर में कोई साम्यता नहीं है, सीआईटी बनाम वी. एमआर. पी. फर्म मुआर [सीआईटी बनाम वी. एमआर. पी. फर्म मुआर, एआईआर 1965 एससी 1216] देखें। यदि किसी कर लगाने वाले कानून में प्रयुक्त शब्द स्पष्ट हैं, तो कोई भी कानून के इरादे और उद्देश्य को जानने की कोशिश नहीं कर सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने स्टाम्प अधिनियम के कथित उद्देश्य और इरादे से जाने की कोशिश करने में और आक्षेपित 1998 के संशोधन से एक पक्ष को होने वाली कठिनाई का पता लगाने की मांग करने में त्रुटि की।

20. *पार्टिंगटन बनाम अटॉर्नी जनरल* [पार्टिंगटन बनाम अटॉर्नी जनरल, (1869) एलआर 4 एचएल 100] में लॉर्ड कैन्स ने निम्नानुसार अवलोकन किया: (एचएल पृष्ठ 122)

‘... यदि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाना है वह कानून के दायरे में आता है तो उस पर कर लगाया जाना चाहिए, भले ही न्यायिक दृष्टिकोण से कठिनाई कितनी ही कठोर या कष्टप्रद क्यों न प्रतीत हो। दूसरी ओर, यदि कर वसूलने की मांग करने वाला राज्य व्यक्ति को कानून के दायरे में नहीं ला सकता है, तो व्यक्ति मुक्त है, हालांकि, मामला अन्यथा कानून की भावना के भीतर दिखाई दे सकता है।’

उपरोक्त अवलोकन को इस न्यायालय द्वारा अक्सर अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है, और हम इसे फिर से समर्थन करते हैं। बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1955 एससी 661] में इस न्यायालय ने माना कि यदि किसी कानून में कठिनाई है तो विधानमंडल को कानून में संशोधन करना है, लेकिन न्यायालय को कठिनाई को कम करने के लिए व्याख्या के मूल नियम को खारिज करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

21. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा सीआईटी बनाम टी.एस. देवनाथ नादर [सीआईटी बनाम टी.एस. देवनाथ नादर, एआईआर 1968 एससी 623] में (एआईआर पैरा 23 से 28 देखें) यह माना गया है कि जहाँ एक कर प्रावधान की भाषा स्पष्ट है, न्यायालय विधानमंडल के इरादे से खुद को चिंतित नहीं कर सकता है। इसलिए, हमारी राय में उच्च न्यायालय ने स्टाम्प अधिनियम में किए गए आक्षेपित संशोधन को अधिनियमित करने में विधानमंडल के इरादे का पता लगाने की कोशिश करने के अपने दृष्टिकोण में त्रुटि की।

22. इस संबंध में हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि जिस तरह धारा 47-ए के तहत संदर्भ को घाटे के शुल्क के 50% के जमा के अधीन किया गया है, उसी तरह विभिन्न कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जिनमें अपील का अधिकार कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है। इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बरकरार रखा गया है जो नीचे नोट किए गए हैं।

23. गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम नगर निगम, अहमदाबाद शहर [गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम नगर निगम, अहमदाबाद शहर, (1999) 4 एससीसी 468] में इस न्यायालय ने विजय प्रकाश डी. मेहता बनाम सीमा शुल्क संग्राहक [विजय प्रकाश डी. मेहता बनाम सीमा शुल्क संग्राहक, (1988) 4 एससीसी 402] में अपने पहले के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें इस न्यायालय ने अवलोकन किया: (विजय प्रकाश का मामला [विजय प्रकाश डी. मेहता बनाम सीमा शुल्क संग्राहक, (1988) 4 एससीसी 402], एससीसी पृष्ठ 406, पैरा 9)

'9. अपील का अधिकार न तो एक पूर्ण अधिकार है और न ही प्राकृतिक न्याय का एक संघटक जिसके सिद्धांतों का पालन सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों में किया जाना चाहिए। अपील का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है और इसे अनुदान में शर्तों द्वारा सीमित किया जा सकता है।'

16. इस प्रस्तुति से निपटते हुए कि उक्त नियम के संदर्भ में, उन मामलों में भी कोई राहत नहीं दी जा सकती है जहाँ पूर्व जमा की आवश्यकता से बहुत पूर्वाग्रह हो सकता है, इस न्यायालय ने अवलोकन करना जारी रखा: (पी. लक्ष्मी देवी का मामला [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720], एससीसी पृष्ठ 736-37, पैरा 28-29)

"28. हम, हालांकि, एक काल्पनिक मामले पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक संपत्ति का सही मूल्य ₹10 लाख है और बिक्री विलेख में यही मूल्य बताया गया है, लेकिन पंजीकरण अधिकारी इसे त्रुटिपूर्ण ढंग से, कहें, ₹2 करोड़ निर्धारित करता है। उस मामले में धारा 47-ए के तहत संग्राहक को संदर्भ करते समय, पंजीकरण अधिकारी ₹10 लाख पर शुल्क की मांग करने के बजाय ₹2 करोड़ के 50% यानी ₹1 करोड़ पर शुल्क की मांग करेगा। एक पक्ष ऐसे मामले में पंजीकरण अधिकारी द्वारा धारा 47-ए के तहत मांगी गई इस अत्यधिक शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस स्थिति में क्या किया जा सकता है?

29. हमारी राय में इस स्थिति में एक पक्ष के लिए हमेशा एक रिट याचिका दायर करने का अवसर होता है जिसमें धारा 47-ए के तहत पंजीकरण अधिकारी द्वारा की गई अत्यधिक मांग को चुनौती दी जाती है, यह आरोप लगाते हुए कि किया गया निर्धारण मनमाना है और/या बाहरी विचारों पर आधारित है, और उस मामले में उच्च न्यायालय के लिए हमेशा यह अवसर होता है कि, यदि वह संतुष्ट है कि आरोप सही है, तो मांग को मनमाना घोषित करके स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत ऐसी अत्यधिक मांग को रद्द कर दे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मनमानी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है (मेनका गांधी बनाम भारत संघ [मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एससीसी 248] देखें)। इसलिए, इस स्थिति में पक्ष उपचारहीन नहीं है।"

17. हर देवी आसनानी [हर देवी आसनानी बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 14 एससीसी 160 : (2012) 4 एससीसी (सिविल) 801] में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65(1) के प्रावधान की वैधता पर विचार किया गया था, जिसके संदर्भ में कोई पुनरीक्षण आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता था जब तक कि यह वसूली योग्य राशि के 50% के भुगतान के संतोषजनक प्रमाण के साथ न हो। पी. लक्ष्मी देवी [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720] सहित इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था और पी. लक्ष्मी देवी [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720] में व्यक्त विचार को हर देवी आसनानी [हर देवी आसनानी बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 14 एससीसी 160 : (2012) 4 एससीसी (सिविल) 801] में दोहराया गया था, जैसा कि निम्नानुसार है: (हर देवी आसनानी [हर देवी आसनानी बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 14 एससीसी 160 : (2012) 4 एससीसी (सिविल) 801], एससीसी पृष्ठ 168, पैरा 27-28)

"27. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720] में इस न्यायालय ने, आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम 8, 1998 द्वारा पेश किए गए स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (1) के प्रावधान को बरकरार रखते हुए, अवलोकन किया: (एससीसी पृष्ठ 737, पैरा 29)

'29. हमारी राय में इस स्थिति में एक पक्ष के लिए हमेशा एक रिट याचिका दायर करने का अवसर होता है जिसमें धारा 47-ए के प्रावधान के तहत पंजीकरण अधिकारी द्वारा की गई अत्यधिक मांग को चुनौती दी जाती है, यह आरोप लगाते हुए कि किया गया निर्धारण मनमाना है और/या बाहरी विचारों पर आधारित है, और उस मामले में उच्च न्यायालय के लिए हमेशा यह अवसर होता है कि, यदि वह संतुष्ट है कि आरोप सही है, तो मांग को मनमाना घोषित करके स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के प्रावधान के तहत ऐसी अत्यधिक मांग को रद्द कर

दे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मनमानी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है (मेनका गांधी बनाम भारत संघ [मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एससीसी 248] देखें)। इसलिए, इस स्थिति में पक्ष उपचारहीन नहीं है।'

28. हमारे विचार में, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के लिए बुलाने हेतु यह पता लगाने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी कि क्या अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण और अतिरिक्त संग्राहक द्वारा अपीलार्थी से की गई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की मांग अत्यधिक थी।”

18. चर्चा के मद्देनजर, यह रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए एक उपयुक्त मामला पाया जाता है।

19. यहाँ ऊपर बताए गए कारणों के लिए, दिनांक 03.08.2015 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

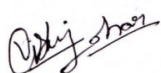
(आशुतोष कुमार), जे.

(अवनीश झिंगन), जे.

सिंपल कुमावत /105

रिपोर्ट योग्य : हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़